अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

रजि.न.34300/80 | संख्या 117 | श्री विजय पुरम, सोमवार, 04 मई 2026 | web: dt.andamannicobar.gov.in | 2.00 रूपए

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ने 'पानी के भीतर सबसे ऊंची मानव स्टैक' का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया

श्री विजय पुरम, 3 मई।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ने उत्कृष्टता की भावना को और भी मजबूत करते हुए आज एक और मील का पत्थर हासिल किया। द्वीप समूह ने 'पानी के भीतर सबसे ऊंची मानव स्टैक' का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। यह रिकॉर्ड स्वराज द्वीप के लाइटहाउस डाइव साइट पर 22.3 मीटर की ऊंचाई पर 3 मिनट की अवधि तक बनी 'मानव स्टैक' के रूप में दर्ज किया गया।

इस कार्यक्रम में अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल एडमिरल डी. के. जोशी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (अ.प्र.) ने भाग लिया। इस अद्वितीय रिकॉर्ड को बनाने में 14 स्कूबा डाइवर्स ने मिलकर 'पानी के भीतर सबसे ऊंची मानव स्टैक' बनाई।

कार्यक्रम के बाद, स्वराज द्वीप के डॉल्फिन रिसॉर्ट के सम्मेलन कक्ष में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के निर्णायक श्री ऋषि नाथ ने नए वर्ल्ड रिकॉर्ड की घोषणा की और अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन को इसका आधिकारिक प्रमाणपत्र प्रदान किया।

मान्नीय उप राज्यपाल ने इस अवसर पर डाइवर्स, अधिकारियों और सभी संबंधित पक्षों की टीमवर्क, समर्पण और प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि इन दोनों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को बनाने में सभी की जबरदस्त मेहनत और सहयोग था। यह रिकॉर्ड ' पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज' (60 मीटर x 40 मीटर, 2,400 वर्ग मीटर) और ' पानी के भीतर सबसे ऊंची मानव स्टैक' (22.3 मीटर ऊंचाई) के रूप में बनाए गए थे।

इन दोनों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रयास अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा द्वीपसमूह के असाधारण जलमग्न धरोहर को उजागर करने और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों को एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय डाइविंग गंतव्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से किए गए थे। इन प्रयासों की सफलता ने द्वीपों की प्रतिष्ठा को और भी मजबूत किया है, और यह अब जलमग्न अन्वेषण और डाइविंग के लिए एक विश्व–स्तरीय गंतव्य बन चुका है।

इस ऐतिहासिक मौके पर वाइस एडमिरल अजय कोचर, एवीएसएम, एनएम, कमांडर–इन–चीफ, अण्डमान तथा निकोबार कमांड, मुख्य सचिव डॉ. चंद्रभूषण कुमार, आईपीएस, पुलिस महानिदेशक श्री एच.एस. धालीवाल, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, पर्यटन विभाग के अधिकारी और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

इस अद्वितीय कार्यक्रम के सफल आयोजन में अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के पर्यटन विभाग, अण्डमान निकोबार पुलिस, वन विभाग, भारतीय नौसेना, भारतीय तट रक्षक और द्वीपसमूह के विभिन्न डाइविंग केंद्रों के स्कूबा डाइवर्स का अहम योगदान रहा। सभी के समर्पण और मेहनत ने इस अभूतपूर्व सफलता को प्राप्त कर पाया।

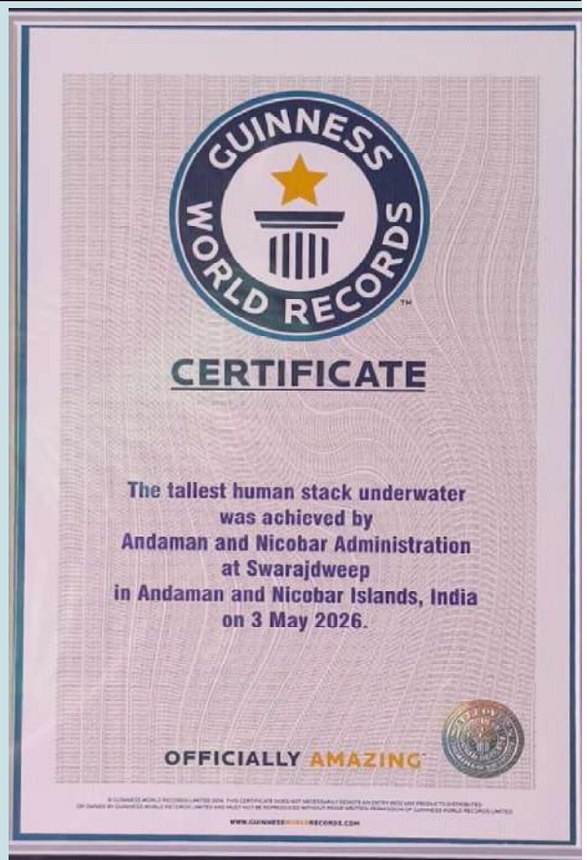

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 लागू–ग्रामीण क्षेत्रों के संस्थानों को बल्क वेस्ट जनरेटर के रूप में पंजीकरण अनिवार्य

श्री विजय पुरम, 3 मई।

ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्थान एवं शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के सभी 70 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सभी संस्थाओं और प्रतिष्ठानों को सूचित किया है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026, 01 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया हैं।

उक्त नियमों के अनुसार, जो भी संस्थाएं महत्वपूर्ण मात्रा में ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करती हैं, उन्हें बल्क वेस्ट जनरेटर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, बस स्टेशन या डिपो, बंदरगाह, औद्योगिक इकाइयां/क्षेत्र, अस्पताल, होटल, बाजार, सामुदायिक सभागार, विवाह हॉल, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और इसी प्रकार की अन्य संस्थाएं शामिल हैं, जो निर्धारित मानदंडों जैसे 20,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक का फ्लोर एरिया; या प्रति दिन 40,000 लीटर पानी की खपत; या प्रति दिन 100 किलोग्राम या उससे अधिक ठोस अपशिष्ट उत्पादन करती हैं।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रावधानों का पालन करते हुए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी ऐसी संस्थाओं से अनुरोध है कि अपने–अपने ग्राम पंचायतों में बल्क वेस्ट जनरेटर के रूप में पंजीकरण/रिपोर्टिंग जल्द से जल्द कराएं। दैनिक अपशिष्ट उत्पादन, प्रबंधन प्रथाओं और उपलब्ध अवसंरचना के संबंध में आवश्यक विवरण प्रदान करें। नियमों का पालन सुनिश्चित करें, जिसमें कचरे का श्रोत पर पृथक्करण, वैज्ञानिक निपटान और स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का पालन शामिल है।

बल्क वेस्ट जनरेटर का पंजीकरण आवश्यक है ताकि, पंचायत स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को सुव्यवस्थित किया जा सके, पर्यावरणीय रूप से उचित कचरा प्रबंधन और निपटान सुनिश्चित किया जा सके, और कानूनी प्रावधानों के अनुपालन और प्रभावी निगरानी को सुगम बनाया जा सके।

ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्थान एवं शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सभी संबंधित संस्थाओं को उपरोक्त निर्देशों का शीघ्रता से पालन करने की सलाह दी जाती है। अनुपालन न करने पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 और स्थानीय उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। अधिक जानकारी और पंजीकरण के लिए संस्थाएं कार्य के समय के दौरान अपने–अपने ग्राम पंचायत कार्यालयों से संपर्क करें।

हुनरहाट–ग्रामीण कौशल और आदिवासी आत्मा का उत्सव

ननकौडी, 3 मई।

कमोर्टा, ननकौडी ब्लॉक में दिनांक 2 मई, 2026 को एक 'एसएचजी हुनरहाट–ग्रामीण कौशल और आदिवासी आत्मा का उत्सव' आयोजित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए एक जीवंत विपणन मंच प्रदान करना था। कमोर्टा और ननकौडी द्वीपों से कई स्वयं सहायता समूह की सदस्यों ने इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया और विभिन्न प्रकार के स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी में पारंपरिक और जातीय खान–पान की वस्तुएं, लकड़ी के हस्तशिल्प, हाथ से बने बरतन और अन्य आदिवासी उत्पाद प्रदर्शित किए गए, जो निकोबार क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और कारीगरी को दर्शाते हैं।

यह कार्यक्रम 'दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' के तहत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए बाजार में दृश्यता बढ़ाना, बिक्री के अवसरों में वृद्धि करना और सतत आजीविका को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए डॉ. क्षितिज ज्ञानराज, सहायक आयुक्त, ननकौडी ने स्वयं सहायता समूह की सदस्यों के पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर पर उद्यमिता को मजबूत करने के प्रयासों की सराहना की। इस कार्यक्रम में

अधिकारियों, स्थानीय निवासियों और समुदाय के सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

हुनरहाट की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि स्थानीय उत्पादों के प्रति जनता की उत्साही प्रतिक्रिया मिली, जिसके परिणामस्वरूप दिन भर में 25,000 रुपये से अधिक की बिक्री हुई, जो स्थानीय रूप से बने उत्पादों के लिए बढ़ते समर्थन को दर्शाता है। यह जानकारी ननकौडी के ब्लॉक विकास अधिकारी, सीडी ब्लॉक ननकौडी से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में दी गई।

नशा मुक्ति के लिए माहव्यापी जागरूकता अभियान आयोजित

श्री विजय पुरम, 3 मई।

नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अभियान को मजबूत करने के उद्देश्य से एंटी–नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन द्वारा 1 अप्रैल, 2026 से 30 अप्रैल, 2026 तक एक महीने का व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। यह अभियान श्री विजय पुरम, स्वराज द्वीप और कदमतला के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किया गया।

इस दौरान कुल 11 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 1199 लोगों ने भाग लिया। इनमें छात्र, युवा, सरकारी कर्मचारी, स्थानीय निवासी, पंचायत प्रतिनिधि और अन्य हितधारक शामिल थे। कार्यक्रम स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों, पंचायतों, पर्यटन स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित किए गए।

अभियान में लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया और मानस हेल्पलाइन–1933 की जानकारी दी गई, जो मानसिक स्वास्थ्य और नशा संबंधित समस्याओं के लिए सहायता और परामर्श प्रदान करती है।

इसके अलावा, पंपलेट वितरण, पोस्टर प्रदर्शन, स्टैंडी लगाना और प्रेरक भाषण जैसे माध्यमों से लोगों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया गया।

डीआईजी (सीआईडी) श्री जितेंद्र कुमार मीणा ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि नशा मुक्त समाज के लिए जनभागीदारी बहुत जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सतर्क रहें और इस अभियान में सहयोग करें। यह अभियान इंस्पेक्टर के. बिनोज के निर्देशन और डीएसपी (नारकोटिक्स)

श्रीमती सुम्मा मड्डा के नेतृत्व में चलाया गया।

अस्थायी जलापूर्ति कार्यक्रम जारी

श्री विजय पुरम, 3 मई

श्री विजय पुरम नगरपालिका परिषद ने शहर में उपलब्ध जल संसाधनों का समान वितरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक अस्थायी जल आपूर्ति कार्यक्रम जारी किया है। आम जानता से अनुरोध है कि वे इस कार्यक्रम का संज्ञान लें और उसी के अनुसार अपने जल उपयोग की योजना बनाएं।

विस्तृत कार्यक्रम एसवीपीएमसी की आधिकारिक वेबसाइट https://pbmc.gov.in/files?id=1072 पर उपलब्ध है तथा क्यूआर कोड स्कैन करके भी देखा जा सकता है।

विकास, विनाश नहीं : निकोबार परियोजना पर पर्यावरण मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 मई।

सरकार ने श्री राहुल गांधी द्वारा ग्रेट निकोबार परियोजना की आलोचना करने के एक दिन बाद, इस पहल का बचाव किया और इसे एक रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजना बताया, जिसका उद्देश्य समग्र विकास करना है।

शुक्रवार को सरकार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों को जोरदार तरीके से नकारा और कहा कि यह एक 'रणनीतिक राष्ट्रीय महत्व' की परियोजना है, जिसका उद्देश्य भारत के समुद्री, आर्थिक और सुरक्षा प्रभाव को इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में मजबूत करना है।

बुधवार को श्री राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान के बाद जारी किए गए एक विस्तृत स्पष्टीकरण में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि यह परियोजना, जो अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के कैम्पबेल बे में प्रस्तावित है, इसे पारिस्थितिकीय सुरक्षा और आदिवासी समुदायों की रक्षा के साथ विकास संतुलित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

मंत्रालय ने कहा कि ग्रेट निकोबार परियोजना का उद्देश्य इस द्वीप को एक प्रमुख समुद्री और आर्थिक हब में बदलना है, जो लगभग 40 नाविक मील की दूरी पर स्थित है और यह अंतरराष्ट्रीय पूर्व–पश्चिम शिपिंग मार्ग के पास स्थित है।

स्पष्टीकरण में कहा गया कि 'ग्रेट निकोबार परियोजना एक रणनीतिक परियोजना है, जिसका उद्देश्य अण्डमान सागर और दक्षिण–पूर्व एशिया में भारत की उपस्थिति को मजबूत करना है। इस परियोजना का उद्देश्य पोर्ट–प्रेरित विकास को पर्यावरणीय सुरक्षा और आदिवासी समुदायों की रक्षा के साथ संतुलित करना है'।

साथ ही साथ यह भी जोड़ा गया कि, 'रणनीतिक, आर्थिक और पारिस्थितिकीय प्राथमिकताओं को मिलाकर, यह परियोजना यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि ग्रेट निकोबार में विकास सतत, समावेशी और राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हो।'

यह महत्वाकांक्षी परियोजना कई बड़े पैमाने पर अवसंरचना विकासों को शामिल करती है। इनमें एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल शामिल है, जिसकी क्षमता 14.2 मिलियन टीईयू है; एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो 4,000 पीक–घंटे के यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा; एक 450 एमवीए गैस और सौर आधारित पावर प्लांट और 16,610 हेक्टेयर में फैला एक नियोजित नगर शामिल है।

मंत्रालय ने कहा कि ये घटक पोर्ट–प्रेरित आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए तैयार किए गए हैं और ग्रेट निकोबार को क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी हब के रूप में स्थापित करने का उद्देश्य रखते हैं।

यह भी जोड़ा गया कि 'आदिवासी कल्याण महत्वपूर्ण है, कोई भी विस्थापन शॉम्पेन और निकोबारी समुदायों के लिए प्रस्तावित नहीं है और आदिवासी आरक्षित क्षेत्र में एक शुद्ध वृद्धि की जाएगी'।

वृक्षों की कटाई को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि परियोजना में अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के कुल वन क्षेत्र का केवल 1.82 प्रतिशत ही हस्तांतरित किया जाएगा। अनुमानित 18.65 लाख पेड़ परियोजना क्षेत्र में हैं, जिनमें से लगभग 7.11 लाख पेड़ 49.86 वर्ग किलोमीटर में चरणबद्ध तरीके से काटे जाने की उम्मीद है।

स्पष्टीकरण में यह भी बताया गया कि परियोजना को पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के तहत पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त है, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और आपदा तैयारी के लिए 42 विशिष्ट अनुपालन शर्तें हैं।

ग्रेट निकोबार में लगभग 237 शॉम्पेन, एक विशेष रूप से संवेदनशील आदिवासी समूह और लगभग 1,094 निकोबारी लोग रहते हैं। सरकार के अनुसार, कोई भी आदिवासी बस्तियाँ विस्थापित नहीं होंगी और मंत्रालयों और आदिवासी कल्याण निकायों के साथ कई एजेंसियों से परामर्श किया गया है।

शेष पृष्ठ 4 पर

प्रमुख असैनिक आपूर्ति वस्तुओं के अवैध भंडारण और असुरक्षित संग्रहण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

श्री विजय पुरम, 3 मई।

नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की प्रवर्तन टीम ने 25 अप्रैल, 2026 को सीपीघाट पंचायत, दक्षिण अण्डमान के बिम्बलीटान गांव में एक आकस्मिक निरीक्षण किया गया। यह संयुक्त अभियान भारतीय तेल निगम लिमिटेड (IOCL) और अण्डमान तथा निकोबार पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एक विशाल एलपीजी सिलेंडरों का भंडार पाया गया। कुल 140 सिलेंडर (भरे हुए और खाली) आवासीय क्षेत्र में बिना अनुमति के और खतरनाक तरीके से संग्रहीत किए गए थे। यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का सीधा उल्लंघन है और यह सार्वजनिक सुरक्षा और आसपास के इलाकों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। जब्त किए गए सिलेंडरों को सुरक्षित रूप से एक अधिकृत एलपीजी भंडारण सुविधा में स्थानांतरित कर दिया गया है। जप्ती के बाद, इसमें शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कानून की संबंधित धाराओं के तहत उचित कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने एलपीजी के अवैध भंडारण और दुरुपयोग के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता नीति की पुनः पुष्टि की है। इस तरह की गतिविधियाँ न केवल आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करती हैं, बल्कि यह अत्यधिक अस्थिर वस्तु होने के कारण जीवन

के लिए भी खतरा उत्पन्न करती हैं। आम जनता से अनुरोध किया जाता है कि वे एलपीजी सिलेंडरों को निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुसार ही संभालें और संग्रहीत करें, अवैध भंडारण में संलिप्त न हों और किसी भी संदिग्ध या अवैध गतिविधियों की सूचना तत्काल अधिकारियों को दें। उपभोक्ता मामलों के उप निदेशक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई कि एलपीजी से संबंधित शिकायतों और कदाचार की रिपोर्ट के लिए एक समर्पित 24ग7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। नागरिक निम्नलिखित चैनलों के माध्यम से त्वरित कार्रवाई के लिए घटनाओं की रिपोर्ट कर सकते हैं :

- टोल–फ्री नंबर : 1800–345–3197
- टेलीफोन नंबर : 03192–230337

"प्रशासन गांव की ओर" कार्यक्रम के तहत कैंप कोर्ट का आयोजन

डिगलीपुर, 3 मई।

"सम्पर्क से समाधान–प्रशासन गांव की ओर" कार्यक्रम के तहत कल ग्राम पंचायत राधानगर के पंचायत भवन में कैंप कोर्ट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री. संतोष प्रकाश, (दानिक्स) सहायक आयुक्त, उत्तर अण्डमान, डिगलीपुर ने की। उनके साथ तहसीलदार डिगलीपुर भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशासन को गांवों तक पहुंचाना, लोगों की समस्याएं सुनना और उनका शीघ्र समाधान करना था।

कैंप कोर्ट में राधानगर पंचायत के जनप्रतिनिधि और आम जनता उपस्थित रहे। इस दौरान नामांतरण, उप–विभाजन, समर्पण जैसे मामलों का निपटारा किया गया और ग्रामीणों तथा पंचायत सदस्यों की विभिन्न शिकायतों को सुना गया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया गया।

इसके बाद सहायक आयुक्त ने राधानगर–1 स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण भी किया, ताकि जमीनी स्तर पर सेवाओं की स्थिति का आकलन किया जा सके। प्रशासन ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे, ताकि लोगों को पारदर्शी और प्रभावी सेवाएं मिल सकें और उनकी समस्याओं का जल्द समाधान हो सके। यह जानकारी सहायक आयुक्त, डिगलीपुर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में दी गई।

विज्ञान केंद्र में हॉलिडे कैंप–2026 का शुभारंभ

श्री विजय पुरम, 3 मई।

विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित हॉलिडे कैंप–2026 का आज गुडविल एस्टेट स्थित सभागार में शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. जय सुंदर उपस्थित थे।

अपने संबोधन में डॉ. जय सुंदर ने कहा कि विज्ञान आज की चुनौतियों का समाधान करने और एक प्रगतिशील समाज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने विज्ञान केंद्र द्वारा ऐसे हॉलिडे कैंप आयोजित करने की सराहना की, जो बच्चों में कम उम्र से ही वैज्ञानिक सोच विकसित करने में मदद करते हैं।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार विज्ञान केंद्र के क्यूरेटर डॉ. मनु वशिष्ठ ने बताया कि इस कैंप में विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी, जैसे प्रायोगिक प्रयोग, इंटरएक्टिव

सत्र और शैक्षणिक भ्रमण इत्यादि। कार्यक्रम की शुरुआत में शिक्षा अधिकारी श्री देबाशीष पॉल ने स्वागत भाषण देते हुए बताया कि इस कैंप में सरकारी और निजी स्कूलों के लगभग 115 छात्र भाग ले रहे हैं। यह कैंप 31 मई, 2026 तक चलेगा।

जेएनआरएम में "भोजन और स्वाद 2के26" सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन

श्री विजय पुरम, 3 मई।

जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय ने 2 मई 2026 को महाविद्यालय फुटबॉल मैदान में "भोजन और स्वाद 2के26" नामक अंतर–विभागीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न विभागों के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जेएनआरएम की प्राचार्या डॉ. पर्ल देवदास थीं। इस अवसर पर एनकॉल के प्राचार्य डॉ. जयकुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।

सांस्कृतिक संध्या में भारत की विविधता की झलक देखने को मिली, जहां चार फूड स्टॉल के माध्यम से बंगाल, तमिलनाडु, केरल और गुजरात के पारंपरिक व्यंजनों को प्रस्तुत किया गया। छात्रों ने अपने–अपने क्षेत्रों की खाद्य संस्कृति का प्रदर्शन किया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। कार्यक्रम में कुल सात समूह नृत्य प्रस्तुत किए गए, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाया गया।

सांस्कृतिक प्रतियोगिता के विजेताओं को नकद पुरस्कार

और ट्रॉफी दी गई। इसमें भूगोल विभाग ने पहला स्थान, अंग्रेजी विभाग ने दूसरा और अर्थशास्त्र विभाग ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं, फूड स्टॉल प्रतियोगिता में अंग्रेजी विभाग ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि बीबीए और होम साइंस विभाग ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सोल ऑफ इंडिया रहा, जो सर्वश्रेष्ठ नृत्य प्रस्तुति के लिए दिया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम की सफलता में योगदान देने वाले छात्र स्वयंसेवकों को भी सम्मानित किया गया।

मदर्स डे पर 'मॉम एंड मी' टीम शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन

श्री विजय पुरम, 3 मई।

अण्डमान निकोबार चेस एसोसिएशन द्वारा मदर्स डे को एक अनोखे और सार्थक तरीके से मनाने के लिए 10 मई, 2026 को श्री विजय पुरम में विशेष 'मॉम एंड मी' टीम शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें माताओं और बच्चों को शतरंज के माध्यम से एक साथ जोड़ा जाएगा।

इस अभिनव आयोजन का उद्देश्य माताओं और उनके बच्चों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करना है। इस विशिष्ट प्रारूप में प्रत्येक टीम में एक मां और उसका बच्चा (पुत्र या पुत्री) शामिल होंगे, जो शतरंज की बिसात पर बारी–बारी से चाल चलते हुए एक टीम के रूप में खेलेंगे। प्रतियोगिता रैपिड प्रारूप में आयोजित की जाएगी, जिससे सभी प्रतिभागियों के लिए उत्साहपूर्ण और रोचक वातावरण सुनिश्चित होगा। यह आयोजन केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि बच्चों के विकास में माताओं की महत्वपूर्ण भूमिका और उनके सहयोग का उत्सव भी है।

इस कार्यक्रम की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें भाग लेने के लिए माताओं के लिए पूर्व शतरंज अनुभव आवश्यक नहीं है, जिससे यह आयोजन सभी के लिए सुलभ और समावेशी बनता है। एसोसिएशन ने सभी माताओं से भाग लेने का आह्वान किया है, ताकि यह परिवारों के लिए एक यादगार अनुभव बन सके।

एएनसीए की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इच्छुक प्रतिभागियों से अनुरोध है कि सीमित सीटों के कारण शीघ्र पंजीकरण कराएं। पंजीकरण एवं अधिक जानकारी के लिए 9933217055 पर संपर्क किया जा सकता है।

विकास, विनाश नहीं : निकोबार परियोजना पर ——————पृष्ठ 1 का शेष

जहां 73.07 वर्ग किलोमीटर आदिवासी आरक्षित भूमि परियोजना उद्देश्यों के लिए डीनोटिफाई की जाएगी, वहीं 76.98 वर्ग किलोमीटर को आदिवासी आरक्षित क्षेत्र के रूप में पुनः अधिसूचित किया जाएगा, जिससे 3.912 वर्ग किलोमीटर की शुद्ध वृद्धि होगी।

आधिकारिक तौर पर कहा गया कि चूंकि यह द्वीप भूकंप, चक्रवातों और सुनामी के प्रति संवेदनशील है, परियोजना में एक समग्र आपदा प्रबंधन और जोखिम मूल्यांकन ढांचा भी शामिल किया गया है। (श्रोत : इंडिया टुडे)।

पुलिस स्टेशन मायाबन्दर द्वारा महात्मा गांधी कॉलेज में लड़कियों की आत्म–रक्षा विषय पर कार्यक्रम

मायाबन्दर, 3 मई।

महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, पुलिस स्टेशन मायाबंदर ने 01.05.2026 से महात्मा गांधी कॉलेज, मायाबंदर की छात्राओं के लिए तीन दिवसीय आत्म–रक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व पुलिस स्टेशन मायाबंदर के प्रशिक्षित ताइक्वांडो मार्शल आर्ट विशेषज्ञों ने किया और इस कार्यक्रम में 136 छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत सुरक्षा और आत्मविश्वास को बढ़ाना था। आत्म–रक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से छात्राओं को शारीरिक सुरक्षा की जानकारी दी गई, वहीं परिस्थितिक जागरूकता को बढ़ावा देने के साथ–साथ चुनौतीपूर्ण स्थितियों में आत्मनिर्भर होने की तैयारी कराई गई। इस कार्यक्रम के द्वारा युवतियों को उनकी सुरक्षा, स्वतंत्रता और समग्र भलाई के लिए आवश्यक जीवन कौशल से

प्रशिक्षित किया गया। यह कार्यक्रम उत्तर तथा मध्य अण्डमान जिले की पुलिस द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति उनके अथक समर्पण और प्रतिबद्धता को उजागर करता है। इसके साथ ही यह समाज में एक सुरक्षित, मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर वातावरण को बढ़ावा देने की दिशा में निरंतर प्रयासों को जारी रखने का प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित करता है।

पुलिस थाना बिल्लीग्राउंड द्वारा त्वरित छापेमारी में अवैध शराब निर्माण व्यवस्था को नष्ट किया

मायाबन्दर, 3 मई।

दिनांक 01.05.2026 को, कारगील टिकरी वन क्षेत्र में अवैध शराब निर्माण की सूचना पर, पुलिस स्टेशन बिल्लीग्राउंड की एक टीम ने तुरंत मौके पर एक खोज अभियान किया। अभियान के दौरान, टीम ने अवैध शराब तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाली लगभग 200 लीटर किण्वित वॉश (लेहन) बरामद की। चूंकि मौके पर कोई भी दावा करने वाला व्यक्ति नहीं था, इसलिए बरामद वॉश और संबंधित सामग्री को साइट पर ही नष्ट कर दिया गया, जो कानूनी प्रक्रिया के अनुसार किया गया। यह अभियान उत्तर एवं मध्य अण्डमान जिला पुलिस की शून्य सहनशीलता नीति और अवैध शराब गतिविधियों के खिलाफ कड़े कार्रवाई के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दोहराता है, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

सामान्य जनता से अनुरोध है कि वे किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि या अवैध गतिविधियों के बारे में विश्वसनीय जानकारी अपने निकटतम पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन नंबर 100, 112 या 03192–273344 के माध्यम से साझा करें। सूचनादाताओं की पहचान को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा और उचित पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

सांसद ने द्वीपसमूह में दूरसंचार नेटवर्क से संबंधित समस्याओं पर शिकायतें, सुझाव एवं अभिमत आमंत्रित किए

श्री विजय पुरम, 3 मई।

सांसद कार्यालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दूरसंचार सलाहकार समिति की एक बैठक शीघ्र ही माननीय सांसद श्री बिष्णु पद रे की अध्यक्षता में बीएसएनएल कार्यालय, श्री विजय पुरम, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में आयोजित की जाएगी।

इस संबंध में, जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपनी शिकायतें, सुझाव एवं अभिमत, यदि कोई हों, 03 दिनों के भीतर अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के सांसद कार्यालय में प्रस्तुत करें या ईमेल **andamanmp@gmail.com** के माध्यम से भेजें। प्राप्त अभिमत प्रस्तावित बैठक के दौरान सार्थक चर्चा में सहायक होंगे। सभी संबंधितों से अनुरोध है कि वे शीघ्र प्रतिक्रिया दें, ताकि द्वीपसमूह में दूरसंचार नेटवर्क सेवाओं से संबंधित समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

गैलेक्सी आई का 'मिशन दृष्टि' सफलतापूर्वक लॉन्च

नई दिल्ली, 03 मई।

बेंगलुरु स्थित एक निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई द्वारा विकसित उपग्रह मिशन दृष्टि रविवार को स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसकी मदद से प्रतिकूल मौसम आपदा के असर, कृषि और सीमा निगरानी से जुड़ी तस्वीरें प्रभावी ढंग से मिल सकेंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पोस्ट के माध्यम से गैलेक्सी आई के संस्थापकों और पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "गैलेक्सी आई द्वारा शुरू किया गया मिशन दृष्टि अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह और भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण, नवाचार और राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारे युवाओं के जुनून का प्रमाण है। गैलेक्सी आई के संस्थापकों और पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।"

रविवार को 190 किलोग्राम वजनी मिशन दृष्टि कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया। यह किसी भारतीय निजी कंपनी द्वारा निर्मित अब तक का सबसे बड़ा उपग्रह है। इस विशेष उपग्रह की विशेषता यह है कि इसमें एक ही उपग्रह पर मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा और सिंथेटिक एपर्चर रडार (एसएआर) इमेजर लगा हुआ है।

दृष्टि मिशन का मूल आधार ऑप्टोसार नामक एक नवीन हाइब्रिड प्रणाली है, जो एक ही प्लेटफॉर्म पर ऑप्टिकल इमेजिंग और सिंथेटिक एपर्चर रडार (एसएआर) को संयोजित करने वाली तकनीक है। परंपरागत रूप से उपग्रह या तो ऑप्टिकल सेंसर या फिर रडार पर निर्भर करते हैं। ऑप्टिकल सिस्टम तस्वीरों के समान विस्तृत और कलर्ड फोटो कैप्चर करते हैं, लेकिन बादल छाए रहने और अंधेरे से ये जमीनी तस्वीर स्पष्ट नहीं मिलती। दूसरी ओर, रडार सिस्टम बादलों के पार देखने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं और रात में भी काम करते हैं, हालांकि वे आमतौर पर कम स्पष्ट छवियां उत्पन्न करते हैं।

ऑप्टो सार एक ही उपग्रह में दोनों तकनीकों को एकीकृत करके इस अंतर को पाटता है। यह एक ही बार में ऑप्टिकल और रडार डाटा को एक साथ कैप्चर करता है, फिर आउटपुट को एक एकीकृत छवि में मिला देता है। परिणामस्वरूप हर मौसम में बादलों के रहते हुए भी पृथ्वी की अत्यंत विस्तृत तस्वीरें मिल सकेंगी। यह भारत के सबसे उच्च–रिजॉल्यूशन वाले उपग्रहों में से एक है।

इस सफल प्रक्षेपण से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में वैश्विक साझेदारियों की बढ़ती भूमिका उजागर होती है। स्पेसएक्स की प्रक्षेपण सेवाओं का लाभ उठाकर, भारतीय स्टार्टअप अत्याधुनिक पेलोड विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए कक्षा तक तेजी से और अधिक लचीली पहुंच प्राप्त कर रहे हैं।

मिशन दृष्टि भारत के अंतरिक्ष परिदृश्य में एक बदलाव का संकेत देता है, जो काफी हद तक सरकार के नेतृत्व से हटकर निजी नवाचार द्वारा संचालित अधिक गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र की ओर अग्रसर है। जैसे–जैसे गैलेक्सी आई उपग्रह की डाटा क्षमताओं को चालू करने की तैयारी कर रहा है, यह मिशन पृथ्वी पर नजर रखने के तरीके को फिर से परिभाषित कर सकता है, जिससे समय या मौसम की परवाह किए बिना स्पष्ट और अधिक विश्वसनीय जानकारी मिल सकेगी।(इनपुट–आईएएनएस)

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) एस. बिजू पिल्लै
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

परिपत्र

यह सामान्य जन की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि चाथम स्थित सरकारी आरा मिल में मांग–पत्रों, आरी से कटी लकड़ी तथा गोल लठ्ठों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का मसौदा तैयार कर लिया गया है तथा इसे टिप्पणियों एवं सुझावों के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रस्तावित एसओपी का उद्देश्य मांग–पत्रों के निस्तारण, आरा संचालन की प्रक्रिया तथा लकड़ी एवं गोल लठ्ठों के भंडारण एवं निपटान के लिए एक पारदर्शी, दक्ष एवं सुव्यवस्थित प्रणाली स्थापित करना है।

विस्तृत मसौदा दस्तावेज सरकारी आरा मिल, चाथम की आधिकारिक वेबसाइट (https://gsmchatham.andamannicobar.gov.in) तथा पर्यावरण एवं वन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://forest.and.nic.in) पर उपलब्ध है।

सभी इच्छुक व्यक्ति/हितधारक/आवेदकगण से अनुरोध है कि वे उक्त वेबसाइटों का अवलोकन कर मसौदा दिशानिर्देशों, उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका एवं प्रक्रियाओं से अवगत हों तथा अपने बहुमूल्य सुझाव एवं टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, प्रस्तुत करें।

टिप्पणियाँ एवं सुझाव दिनांक 10 मई, 2026 तक ईमेल frychatham052@gmail.com के माध्यम से प्रेषित किए जा सकते हैं।

निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त सभी सुझावों एवं टिप्पणियों पर समुचित विचार किया जाएगा, जिसके उपरांत एसओपी को अंतिम रूप देकर पृथक रूप से अधिसूचित किया जाएगा।

उप वन संरक्षक, मिल प्रभाग चाथम

ई–निविदा सूचना

कार्यपालक अभियंता, पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान, प्रधान, ग्राम पंचायत, नील केन्द्र, शहीद द्वीप की ओर से, निम्नलिखित कार्यों के लिए उचित श्रेणी के योग्य व अनुभवी ठेकेदारों से मुहरबंद मद दर (के.लो.नि.वि.–8 के प्रपत्र के रूप में) आमंत्रित करते है।

एन. आई. टी. संख्या : क.अ./पी आर आई/एस ए डी–।/आर आर/2026–27/17

कार्य का नाम : नील केन्द्र ग्राम पंचायत के अंर्तगत भरतपुर 2 में दिलिप बासु के घर के पास मौजूदा सी सी रोड से लेकर स्वर्गीय खितिश राय के घर तक जल शोधन संयंत्र होते हुए सी सी रोड का निर्माण कार्य।

अनुमानित लागत : रु. 6,61,628/–, धरोहर राशि : रु. 13,233/–, कार्य समाप्ति की अवधि : (03) तीन माह।

निविदा शुल्क : रु. 500/–, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 08/05/2026 के अपराहन 3.00 बजे तक।

निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।

टेंडर आई डी : 2026_RDPRI_22859_1

कार्यपालक अभियंता,
पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।,
जंगलीघाट, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान

ई–निविदा सूचना

कार्यपालक अभियंता, पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान, प्रधान, ग्राम पंचायत, बम्बूफ्लाट–।।, की ओर से, निम्नलिखित कार्यों के लिए उचित श्रेणी के योग्य व अनुभवी ठेकेदारो से मुहरबंद मद दर (के.लो.नि.वि.–8 के प्रपत्र के रूप में) आमंत्रित करते है।

एन. आई. टी. संख्या : क.अ./पी आर आई/एस ए डी–।/जीईएन/2026–27/26

कार्य का नाम : बम्बूफ्लाट–।।, ग्राम पंचायत के अंर्तगत एसडब्ल्यूएम के लिए सेगरिगेशन शेड का निर्माण कार्य।

अनुमानित लागत : रु. 8,91,207/–, धरोहर राशि : रु. 17,824/–, कार्य समाप्ति की अवधि : (04) चार माह।

निविदा शुल्क : रु. 500/–, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 08/05/2026 के अपराहन 3.00 बजे तक।

निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।

टेंडर आई डी : 2026_RDPRI_22844_1

कार्यपालक अभियंता,
पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।,
जंगलीघाट, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान

ई–निविदा सूचना

कार्यपालक अभियंता, पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान, प्रधान, ग्राम पंचायत, गोविन्द नगर, स्वराज द्वीप की ओर से, निम्नलिखित कार्यों के लिए उचित श्रेणी के योग्य व अनुभवी ठेकेदारो से मुहरबंद मद दर (के.लो.नि.वि.–8 के प्रपत्र के रूप में) आमंत्रित करते है।

एन. आई. टी. संख्या : क.अ./पी आर आई/एस ए डी–।/जीईएन/2026–27/24

कार्य का नाम : स्वराज द्वीप, गोविन्द नगर ग्राम पंचायत के अंर्तगत वार्ड न. 02 विजय नगर में आबंटित मकान स्थल पर पीएमएवाई.जी योजना के तहत सभी प्रकार के सी सी फुटपाथ का निर्माण कार्य।

अनुमानित लागत : रु. 15,89,875/–, धरोहर राशि : रु. 31,798/–, कार्य समाप्ति की अवधि : (06) छह माह।

निविदा शुल्क : रु. 500/–, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 08/05/2026 के अपराहन 3.00 बजे तक।

निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।

टेंडर आई डी : 2026_RDPRI_22871_1

कार्यपालक अभियंता,
पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।,
जंगलीघाट, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान

ई–निविदा सूचना

कार्यपालक अभियंता, पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान, प्रमुख, पंचायत समिति, प्रात्रापुर की ओर से, निम्नलिखित कार्यों के लिए उचित श्रेणी के योग्य व अनुभवी ठेकेदारो से मुहरबंद मद दर (के.लो.नि.वि.–8 के प्रपत्र के रूप में) आमंत्रित करते है।

एन. आई. टी. संख्या : क.अ./पी आर आई/एस ए डी–।/आर आर (सीसीए)/2026–27/10

कार्य का नाम : प्रात्रापुर पंचायत समिति द्वारा कलिकट वार्ड न. 03 में सेवन हिल्स रोड से विनोद के घर होते हुए नायडू के घर तक ग्रामीण सड़क का निर्माण कार्य।

अनुमानित लागत : रु. 20,32,518/–, धरोहर राशि : रु. 40,650/–, कार्य समाप्ति की अवधि : (06) छह माह।

निविदा शुल्क : रु. 500/–, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 08/05/2026 के अपराहन 3.00 बजे तक।

निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।

टेंडर आई डी : 2026_RDPRI_22886_1

कार्यपालक अभियंता,
पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।,
जंगलीघाट, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान

शपथ–पत्र

मैं, ट्विंकल घोष, पत्नी श्री जयंता कुमार घोष, निवासी माउंट रेजिडेंशियल कॉलोनी, वार्ड नं. 17, डॉलीगंज, थाना पहाड़गाँव, तहसील श्री विजय पुरम, जिला दक्षिण अण्डमान, यह शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करती हूँ :–

1. कि मेरी 10वीं कक्षा की अंक तालिका, जिसका सीरियल नंबर A/03067919 तथा रोल नंबर 22A822036 है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नई दिल्ली द्वारा जारी की गई है, उसमें मेरे पिता का नाम गलत रूप से डिकी डे अंकित है।
2. कि मेरे पिता का सही एवं वास्तविक नाम दीपक ज्योति डे है, जैसा कि आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड संख्या CLYPG1348A में दर्ज है।
3. कि मुझे अपनी 10वीं की अंकतालिका में अपने पिता के नाम में संशोधन करवाना है, जो पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया हेतु आवश्यक है।
4. कि डिकी डे तथा दीपक ज्योति डे एक ही व्यक्ति है।
5. कि मैं यह शपथ–पत्र अपने पिता के नाम को 10वीं की अंकतालिका में दीपक ज्योति डे के रूप में संशोधित कराने के उद्देश्य से प्रस्तुत कर रही हूँ।

यह कि उपरोक्त अनुच्छेद 1 से 5 तक के सभी कथन मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं।

शपथकर्ता

खबरों और रोचक जानकारियों के लिए पढ़िए
'द्वीप समाचार'

पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में आज होगी मतगणना

नई दिल्ली, 03 मई।

पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना कल होगी। असम की 126, केरल की 140 और पुद्दुचेरी की 30 सीट के लिए मतदान 9 अप्रैल को हुआ था। तमिलनाडु की 234 सीटों के लिए 23 अप्रैल को और पश्चिम बंगाल की 293 सीटों के लिए दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले गए थे।

काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस पर फोकस करेंगे भारत व कंबोडिया के जवान

नई दिल्ली, 03 मई।

भारत व कंबोडिया काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस पर फोकस करने जा रहे हैं। यह भारत की सैन्य कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण आयाम है। इसके तहत रविवार को भारतीय सैन्य दल, भारत–कंबोडिया संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास 'सिनबैक्स–टी 2026' के लिए कंबोडिया रवाना हुआ है।

यह युद्धाभ्यास कंबोडिया में आयोजित किया जाएगा। यहां दोनों देशों के जवान आतंकवाद–रोधी अभियानों, जंगल एवं अर्ध–शहरी क्षेत्रों में ऑपरेशन व समन्वित रणनीतियों पर मिलकर अभ्यास करेंगे। दोनों देशों का यह संयुक्त अभ्यास भारतीय सेना और रॉयल कंबोडियन आर्मी के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग का महत्वपूर्ण प्रतीक है।

सिनबैक्स का मुख्य उद्देश्य कंपनी स्तर पर संयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से सब–कन्वेंशनल (अपरंपरागत) वातावरण में सैन्य अभियानों को और अधिक प्रभावी बनाना है।

इस अभ्यास के दौरान सैनिक एक–दूसरे के अनुभवों से सीखेंगे, आधुनिक तकनीकों और रणनीतियों का आदान–प्रदान करेंगे और जमीनी स्तर पर तालमेल को मजबूत करेंगे। खास बात यह है कि इसमें काउंटर–टेररिज्म ऑपरेशंस पर विशेष जोर दिया जाएगा। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि काउंटर–टेररिज्म ऑपरेशंस आज के वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में बेहद महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि सिनबैक्स केवल एक सैन्य अभ्यास भर नहीं, बल्कि भारत की उस व्यापक सोच का हिस्सा है, जिसमें वह क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

यह अभ्यास न केवल दोनों देशों के बीच सैन्य साझेदारी को सुदृढ़ करेगा, बल्कि आपसी विश्वास, समझ और सहयोग को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। दरअसल, भारत और कंबोडिया के बीच यह सहयोग यह दर्शाता है कि दोनों देश मिलकर न केवल अपनी सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। यह अभ्यास 4 मई से प्रारंभ होगा और 17 मई 2026 तक कंबोडिया साम्राज्य के कंम्पोंग स्पेयू प्रांत स्थित टेको सेन नोम थॉम म्रीस प्रॉव रॉयल कंबोडियन एयर फोर्स प्रशिक्षण केंद्र (कैंप बेसिल) में जारी रहेगा। मित्र देशों के साथ चल रहे भारत के रक्षा सहयोग के अंतर्गत कंबोडिया के साथ यह द्विपक्षीय अभ्यास 'सिनबैक्स–द्वितीय' वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के बदलते परि.श्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के अध्याय आठ के ढांचे के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना के दल में 120 सैन्यकर्मी शामिल हैं। इस सैन्य दल में अधिकांश जवान मराठा लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन से हैं। वहीं कंबोडियाई दल की बात करें तो यह 160 कार्मिकों का एक विशेष सैन्य दल है। ये सभी जवान रॉयल कंबोडियन आर्मी से हैं।

भारत का मेडिकल टूरिज्म बाजार 2030 तक दोगुना होकर 16.2 अरब तक पहुंचने की उम्मीद

नई दिल्ली, 03 मई।

सरकार ने शनिवार को कहा कि भारत 'मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (एमवीटी)' यानी मेडिकल टूरिज्म का एक बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है, और मेडिकल टूरिज्म बाजार 2025 में लगभग 8.7 अरब डॉलर से बढ़कर 2030 तक करीब 16.2 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। वैश्विक स्तर पर एमवीटी बाजार 2022 में करीब 115.6 अरब डॉलर का था, जो 2030 तक लगभग 286.1 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें सालाना करीब 10.8 प्रतिशत की वृद्धि दर (सीएजीआर) रहने की संभावना है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि दुनिया भर में बढ़ती स्वास्थ्य सेवाओं की लागत, लंबा इंतजार और लाइफस्टाइल बीमारियों के बढ़ते बोझ के कारण लोग इलाज के लिए विदेशों का रुख कर रहे हैं। भारत में एमवीटी (मैच्योर व्हीकल थेरेपी) का उदय आयुष जैसी पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों के साथ उन्नत चिकित्सा अवसंरचना के एकीकरण से प्रेरित है। इसके अलावा मजबूत नीतिगत समर्थन, डिजिटल सुविधाओं और आयुष वीजा व क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों जैसी पहल से इस सेक्टर को मजबूती मिल रही है।

भारत का एमवीटी सिस्टम दो हिस्सों में काम करता है. एक, गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मेडिकल टूरिज्म और दूसरा, योग और आयुर्वेद जैसी आयुष पद्धतियों पर आधारित वेलनेस टूरिज्म। यह दोनों मिलकर उन्नत इलाज और बढ़ती रोकथाम (प्रिवेंटिव हेल्थकेयर) की जरूरतों को पूरा करते हैं। 2025 में भारत में 9.15 मिलियन विदेशी पर्यटक आए, जिनमें से 5,07,244 लोग इलाज के लिए आए थे। यानी कुल विदेशी पर्यटकों में मेडिकल टूरिज्म की हिस्सेदारी लगभग 5.5 प्रतिशत रही।

वर्ष 2025 में मेडिकल टूरिज्म के लिए भारत आने वाले प्रमुख देशों में बांग्लादेश (325,127), इराक (30,989), उज्बेकिस्तान (13,699), सोमालिया (11,506), तुर्कमेनिस्तान (10,231), ओमान (9738) और केन्या (9,357) शामिल रहे। मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स 2020–21 के अनुसार, भारत दुनिया के 46 प्रमुख मेडिकल टूरिज्म देशों में 10वें स्थान पर रहा, जबकि एशिया–प्रशांत क्षेत्र के टॉप 10 वेलनेस डेस्टिनेशन में पांचवें स्थान पर है।

भारत की स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत गुणवत्ता मानकों और अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रमाणन प्रणाली से समर्थित हैं। देश भर के अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता राष्ट्रीय अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) से मान्यता प्राप्त करते हैं, जो मरीजों की सुरक्षा और इलाज की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।

2000 रुपए के नोटों की वापसी की घोषणा के बाद से 98.47 प्रतिशत नोट वापस आ चुके हैं– आरबीआई

नई दिल्ली, 03 मई।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि 2000 रुपए के 98.47 प्रतिशत नोट वापस आ चुके हैं। यह आंकड़ा नोटों को चलन से हटाने की घोषणा के लगभग तीन साल बाद सामने आया है। केंद्रीय बैंक ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोटों को चलन से हटाने का फैसला लिया था, जो उसकी मुद्रा प्रबंधन प्रक्रिया का हिस्सा था।

उस समय इन नोटों की कुल वैल्यू 3.56 लाख करोड़ रुपए थी। लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, यह घटकर 30 अप्रैल 2026 तक सिर्फ 5,451 करोड़ रुपए रह गई है। आरबीआई ने कहा, 19 मई 2023 को जब 2000 रुपए के नोट वापस लेने की घोषणा की गई थी, तब इनकी कुल वैल्यू 3.56 लाख करोड़ रुपए थी, जो अब घटकर 5,451 करोड़ रुपए रह गई है।

आरबीआई ने अपने बयान में कहा, इस तरह 19 मई 2023 तक चलन में मौजूद 2000 रुपए के 98.47 प्रतिशत नोट वापस आ चुके हैं। नोटों को वापसी लेने की घोषणा के बाद से देश भर में आरबीआई के 19 इश्यू ऑफिस में 2000 रुपए के नोट बदलने की सुविधा दी गई है।

9 अक्टूबर 2023 से इन ऑफिसों में इन नोटों को बैंक खाते में जमा करने की सुविधा भी शुरू कर दी गई थी। केंद्रीय बैंक ने यह भी बताया कि लोग अब भी देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस से इंडिया पोस्ट के जरिए 2000 रुपए के नोट आरबीआई के इश्यू ऑफिस में भेज सकते हैं, ताकि उन्हें उनके बैंक खाते में जमा किया जा सके।

आरबीआई ने कहा, ष्9 अक्टूबर 2023 से आरबीआई के इश्यू ऑफिस में व्यक्ति और संस्थाएं 2000 रुपए के नोट अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं। केंद्रीय बैंक ने आगे कहा कि इसके अलावा, लोग देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस से इंडिया पोस्ट के जरिए 2000 रुपए के नोट आरबीआई के किसी भी इश्यू ऑफिस में भेजकर अपने खाते में जमा करा रहे हैं। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि चलन से हटाए जाने के बावजूद 2000 रुपए के नोट अभी भी वैध मुद्रा (लीगल टेंडर) बने हुए हैं।

इतिहास के पन्नों में 04 मई

नई दिल्ली, 03 मई।

साल के बाकी दिनों की तरह चार मई ने भी कई घटनाओं के कारण इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। ब्रिटेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप की पहली महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर को दुनिया में आयरन लेडी के तौर पर जाना जाता है। उन्हें चार मई के दिन ही ब्रिटेन की प्रधानमंत्री चुना गया था।

इस दिन से जुड़ी कुछ अन्य घटनाओं की बात करें तो लंदन डेली मेल का पहला संस्करण चार मई को ही प्रकाशित हुआ था और आस्कर पुरस्कार देने वाली मोशन पिक्चर्स आटर्स एकेडमी की स्थापना भी अमेरिका में चार मई के दिन ही हुई थी। देश दुनिया के इतिहास में 4 मई की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है:–

1799– मैसूर के टीपू सुल्तान की श्रीरंगपत्तनम की लड़ाई में मृत्यु।

1854– भारत की पहली डाक टिकट को औपचारिक तौर पर जारी किया गया।

1896– लंदन डेली मेल का पहला संस्करण प्रकाशित।

1924– पेरिस में आठवें ओलिम्पिक खेलों की शुरूआत।

1945– जर्मनी की सेना ने नीदरलैंड, डेनमार्क और नार्वे में आत्मसमर्पण किया।

1980– इस दिन को कोल माइंस डे के तौर पर मनाने की घोषणा।

1927– अमरीका में फिल्म कला अकादमी (मोशन पिक्चर आर्ट्स एकेडेमी) की स्थापना, जिसने 'ऑस्कर' पुरस्कार देने शुरू किए।

1928– करीब तीन दशक तक मिस्र के राष्ट्रपति रहे हुस्नी मुबारक का जन्म

1945– जर्मनी की सेना ने नीदरलैंड, डेनमार्क और नार्वे मे आत्मसमर्पण किया।

1959– पहले ग्रैमी अवॉर्ड्स का आयोजन।

1975– 'द किड' और 'ग्रेट डिक्टेटर' जैसी मूक फिल्मों के स्टार चार्ली चौपलिन को बकिंघम पैलेस में नाइट की उपाधि प्रदान की गई।

1979– मार्गरेट थैचर को ब्रिटेन की प्रधानमंत्री चुना गया। पूरे यूरोप में वह यह पद संभालने वाली पहली महिला थीं।

1980– जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति नेता रॉबर्ट मुगाबे ने चुनाव में भारी जीत हासिल की और प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने।

1983– चीन ने परमाणु परीक्षण किया।

2006– नेपाल के माओवादी विद्रोहियों ने देश की नयी सरकार के साथ शांति वार्ता में भाग लेने पर सहमति जताई।

2020– देश में कोविड–19 के कारण मौत के मामले 1,389 हो गए और संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 42,836 पर पहुंच गयी।

1975– 'द किड' और 'ग्रेट डिक्टेटर' जैसी मूक फिल्मों के स्टार चार्ली चैपलिन को बकिघम पैलेस में नाइट की उपाधि प्रदान की गई।

झीलों–नदियों से पहाड़ों तक, ऐसे लिखें पृथ्वी की खूबसूरती पर अपना नाम, नासा के मजेदार लैंडसेट सर्विस के लिए फॉलो करें ये स्टेप

नई दिल्ली, 03 मई (आईएएनएस)।

अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की पृथ्वी दिवस के अवसर पर एक रोचक और अनोखी शुरू की गई सर्विस की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। अब आप अपनी पसंद का नाम लैंडसेट उपग्रह की तस्वीरों में पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे झीलें, नदियों, रेगिस्तान और पहाड़ों पर देख सकते हैं।

नासा की यह सर्विस 'योर नेम इन लैंडसेट' नाम से शुरू की गई है। इसमें यूजर्स अपना नाम अंग्रेजी अक्षरों में टाइप करते हैं और सिस्टम अपने आप नाम के हर अक्षर को लैंडसेट सैटेलाइट द्वारा ली गई असली धरती की तस्वीरों से मिलाकर एक सुंदर ग्राफिक बना देता है। लैंडसेट कार्यक्रम 50 वर्ष से अधिक पुराना है और यह पृथ्वी की निगरानी के लिए सबसे लंबे समय से चल रहे उपग्रह कार्यक्रमों में से एक है। इन तस्वीरों में इस्तेमाल की गई छवियां नासा अर्थ ऑब्जर्वेटरी, नासा वर्ल्ड व्यू, यूएसजीएस अर्थ एक्सप्लोरर और ईएए सेंटीनल हब से ली गई हैं।

यह इंटरैक्टिव टूल न सिर्फ मनोरंजन के लिए है, बल्कि लोगों को लैंडसेट कार्यक्रम और पृथ्वी के बारे में जागरूक करने का भी एक अच्छा माध्यम है। हर अक्षर के लिए अलग–अलग प्राकृतिक पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है, जो पृथ्वी की विविधता को दिखाता है। नासा का कहना है कि यह सेवा पृथ्वी की सुंदरता को आम लोगों तक पहुंचाने और उन्हें सैटेलाइट इमेजरी से जोड़ने का एक

रचनात्मक प्रयास भी है।

अब सवाल है कि अपना नाम लैंडसेट पर कैसे देखें? तो इसके लिए नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पर चरणबद्ध तरीके से जानकारी दी गई है। इसके लिए सबसे पहले नासा की आधिकारिक वेबसाइट पर 'योर नेम इन लैंडसेट' पेज पर जाएं। वहां अपना नाम दर्ज करें, वहां दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में अपना नाम अंग्रेजी कैपिटल अक्षरों (ए–जेड) में टाइप करें।

इसके बाद एंटर बटन दबाएं या सब्मिट पर क्लिक कर जनरेट करें। इसके कुछ ही सेकंड में आपके नाम के अक्षर पृथ्वी की खूबसूरत भौगोलिक विशेषताओं जैसे नीली झीलें, हरे–भरे क्षेत्र, रेगिस्तानी पैटर्न या बर्फ से ढके पहाड़ से बने हुए दिखाई देंगे। इसके बाद बनी हुई इस खास कलाकृति को डाउनलोड करके सेव या शेयर भी कर सकते हैं।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2.0 लॉन्च, बच्चों के समग्र स्वास्थ्य के लिए नए दिशानिर्देश जारी

नई दिल्ली, 03 मई।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को 'सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण में सर्वोत्तम प्रथाओं' पर आयोजित राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) 2.0 के नए और संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। यह पहल देश में बच्चों के स्वास्थ्य और समग्र विकास को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मंत्रालय की ओर से बताया गया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पहले से लागू '4–डी मॉडल' को और अधिक मजबूत बनाना है। इस मॉडल के तहत चार प्रमुख श्रेणियों जन्मजात दोष, रोग, कमियां, कुपोषण और विकासात्मक विलंब पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

नए दिशा–निर्देशों में आधुनिक समय की स्वास्थ्य चुनौतियों को भी शामिल किया गया है। इनमें गैर–संक्रामक रोग, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं और व्यवहार संबंधी विकार प्रमुख हैं। इस तरह कार्यक्रम अब पारंपरिक स्वास्थ्य समस्याओं के साथ–साथ बदलती जीवनशैली से जुड़ी चुनौतियों का भी समाधान करेगा।

संशोधित ढांचे में बच्चों के लिए निवारक, प्रोत्साहक और उपचारात्मक सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला को शामिल किया गया है। यह कार्यक्रम जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को कवर करता है और जीवन चक्र–आधारित दृष्टिकोण को और अधिक प्रभावी बनाता है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इन दिशानिर्देशों के सफल क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिलकर कार्य करेंगे। साथ ही, स्कूलों व आंगनवाड़ी केंद्रों को स्क्रीनिंग और जागरूकता के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से अखिल भारतीय 'अग्नि सुरक्षा सप्ताह' मनाएगा

नई दिल्ली, 03 मई।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय 'अग्नि सुरक्षा सप्ताह' मनाएगा। इसका उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन करेंगी और उनके नेतृत्व में स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि सुरक्षा की शपथ दिलाई जाएगी।

ट्राई ने सार्वजनिक वाई–फाई नेटवर्क पर 25 मई तक मांगे सुझाव

नई दिल्ली, 03 मई।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने देश में सार्वजनिक वाई–फाई नेटवर्क के प्रसार पर परामर्श पत्र जारी कर 25 मई तक लोगों से सुझाव मांगें हैं। ट्राई के मुताबिक पत्र में मौजूदा नियामक ढांचे की समीक्षा की गई है, सार्वजनिक वाई–फाई नेटवर्क के विस्तार में आ रही चुनौतियों की पहचान कर देशभर में वाई–फाई अवसंरचना को तेजी से बढ़ाने के उपायों पर हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं। लोगों से 25 मई तक लिखित टिप्पणियां और 8 जून 2026 तक प्रत्युत्तर टिप्पणियां देने को कहा गया है।

पत्र में प्राधिकरण, प्रमाणीकरण, रोमिंग और बिलिंग सिस्टम से जुड़ी समस्याओं के साथ–साथ राजस्व मॉडल का विश्लेषण किया गया है, ताकि सार्वजनिक वाई–फाई नेटवर्क को टिकाऊ बनाया जा सके। परामर्श पत्र में अन्य देशों के सार्वजनिक वाई–फाई तंत्र का अवलोकन, भारत में वर्तमान स्थिति, तैनाती के रुझान और मांग पैटर्न का आकलन शामिल है। इसमें प्रमुख चुनौतियों, अधिक भीड़भाड़ वाले स्थानों, ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी केंद्रों में सार्वजनिक वाई–फाई मॉडल विकसित करने में केंद्र व राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और निजी संस्थाओं की भूमिका पर विचार किया गया है।

विदेशों में भी तेजी से पसंद किए जा रहे हैं, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद

नई दिल्ली, 03 मई।

भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद अब सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी तेजी से पसंद किए जा रहे हैं। इसका सीधा असर देश के निर्यात आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 2025 में 4 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है। यह उपलब्धि ऐसे समय आई है, जब वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। इस रिकॉर्ड बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण मोबाइल फोन विनिर्माण, खासकर एप्पल के आईफोन निर्यात में आई जबरदस्त तेजी और सरकार की अनुकूल नीतियां मानी जा रही हैं।

आंकड़े बताते हैं कि भारत से होने वाला आईफोन निर्यात 2025 में 2.03 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो 2024 के 1.1 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले लगभग दोगुना है। यही नहीं, देश में बनने वाले हर चार में से एक स्मार्टफोन का निर्यात अब विदेशों में हो रहा है।

इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के अंत तक केवल मोबाइल फोन का निर्यात 2.7 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। यह संकेत है कि भारत धीरे–धीरे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है।

इस तेजी का सबसे बड़ा फायदा देश की अर्थव्यवस्था को मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में लाखों नए रोजगार पैदा हो रहे हैं, वहीं भारत को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हो रही है। इससे न केवल उद्योग मजबूत हो रहे हैं, बल्कि आम लोगों के लिए भी रोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं।

भविष्य की बात करें तो सेमीकंडक्टर क्रांति भारत के इलेक्ट्रॉनिक निर्यात को और नई रफ्तार दे सकती है। वर्ष 2026 में चार नए सेमीकंडक्टर संयंत्र व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने जा रहे हैं, जिससे आयात पर निर्भरता घटेगी और निर्यात क्षमता और बढ़ेगी।

वैश्विक स्तर पर चीन पर अमेरिकी शुल्क और बड़ी कंपनियों की 'चीन प्लस वन' रणनीति का सीधा लाभ भारत को मिल रहा है। नील शाह (काउंटरपॉइंट) के अनुसार, आने वाले समय में भारत में मोबाइल उत्पादन 30 करोड़ यूनिट तक पहुंच सकता है।

भारत से होने वाले आईफोन निर्यात में साल–दर–साल लगभग 100% की वृद्धि दर्ज की गई है। एप्पल आज भी प्रीमियम और सुपर–प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है, जिससे भारत की साख वैश्विक बाजार में और मजबूत हो रही है।

पृथ्वी के अस्तित्व के लिए जरूरी है सूर्य, जानें सूरज की रोशनी से कैसे बनती है बिजली? कैसे काम करता है 'सोलर पावर'

नई दिल्ली, 03 मई।

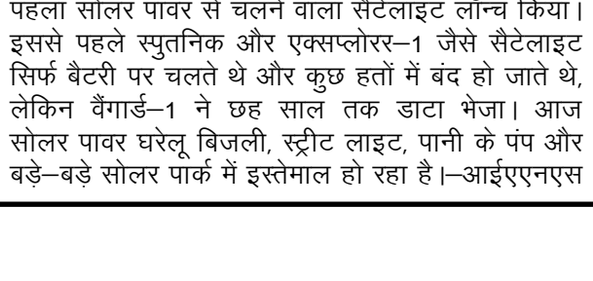

पृथ्वी पर जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। अनाज से लेकर जलवायु, मौसम नियंत्रण तक में इसकी भागीदारी है। पूरी मानव जाति एक साल में जितनी ऊर्जा इस्तेमाल करती है, उतनी ऊर्जा सूर्य सिर्फ एक घंटे में पृथ्वी को दे देता है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में जब दुनिया ऊर्जा संकट और प्रदूषण से जूझ रही है, तब सूर्य की रोशनी से बिजली बनाने वाली सौर ऊर्जा सबसे सस्ता, साफ और अनलिमिटेड विकल्प बनकर उभरी है। 3 मई को हर साल अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाया जा रहा है, जो सौर ऊर्जा के महत्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।

सौर ऊर्जा को बिजली में बदलने की प्रक्रिया को 'सोलर पावर' कहते हैं। यह तकनीक लगभग 200 साल पुरानी है, लेकिन आज यह घरों से लेकर अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है। सोलर पावर न सिर्फ बिजली पैदा करती है बल्कि पर्यावरण को भी बचाती है क्योंकि इसमें कोई धुआं, प्रदूषण या आवाज नहीं होती। सिर्फ सूरज की रोशनी काफी है।

अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अनुसार, सोलर पावर का मतलब है सूरज की रोशनी को बिजली में बदलना। यह प्रक्रिया 'फोटोवोल्टिक इफेक्ट' पर आधारित है। सन 1839 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर एडमंड बेकरेल (उस समय सिर्फ 19 साल के थे) ने सबसे पहले इस प्रभाव की खोज की। वे अपने पिता की लैब में प्रयोग कर रहे थे। जब उन्होंने रोशनी पर काम किया तो बिजली का करंट पैदा हुआ। यही घटना सोलर पावर की नींव बनी।

वैज्ञानिक बताते हैं कि सोलर पैनल मुख्य रूप से सिलिकॉन नामक सामग्री से बनाए जाते हैं। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, यानी यह बिजली को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। एक सामान्य सोलर सेल में सिलिकॉन की तीन पतली परतें होती हैं। बीच वाली परत प्योर सिलिकॉन की होती है। ऊपरी और निचली परतों में थोड़े अलग तत्व मिलाए जाते हैं जैसे एक तरफ फास्फोरस और दूसरी तरफ बोरॉन। जब सूरज की रोशनी इन परतों पर पड़ती है तो सिलिकॉन के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं और घूमने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक परत से दूसरी परत की ओर खिंचते हैं। इससे एक तरफ नेगेटिव चार्ज और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज जमा होता है। दोनों तरफ तार लगाकर सर्किट बनाया जाता है। इलेक्ट्रॉन इस सर्किट से बहते हुए बिजली पैदा करते हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं।

खास बात है कि इस पूरी प्रक्रिया में कोई धुआं, प्रदूषण या आवाज नहीं होती। सिर्फ सूरज की रोशनी चाहिए होती है और बीजली पैदा हो जाती है। सोलर पैनल इतने उपयोगी हैं कि स्पेस एजेंसी इन्हें अंतरिक्ष यानों में भी इस्तेमाल करते हैं। नासा के अनुसार, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी सोलर पैनल से ही बिजली प्राप्त करता है।

नासा लगातार सोलर टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने का काम कर रहा है। अंतरिक्ष में सोलर पावर की शुरुआत की बात करें तो सोलर सेल का पहला सफल इस्तेमाल 1958 में हुआ था। अमेरिका ने मार्च 1958 में वैंगार्ड–1 नाम का पहला सोलर पावर से चलने वाला सैटेलाइट लॉन्च किया। इससे पहले स्पुतनिक और एक्सप्लोरर–1 जैसे सैटेलाइट सिर्फ बैटरी पर चलते थे और कुछ हतों में बंद हो जाते थे, लेकिन वैंगार्ड–1 ने छह साल तक डाटा भेजा। आज सोलर पावर घरेलू बिजली, स्ट्रीट लाइट, पानी के पंप और बड़े–बड़े सोलर पार्क में इस्तेमाल हो रहा है।–आईएएनएस

भारत के इस राज्य ने रचा इतिहास, देश की पहली 'पेपरलेस न्यायपालिका' बनकर पेश की नजीर

गंगटोक, 03 मई।

भारतीय न्याय प्रणाली में एक नए और पारदर्शी युग की शुरुआत हो गई है। सिक्किम ने देश का पहला 'पेपरलेस न्यायपालिका' (Paperless Judiciary) राज्य बनकर इतिहास रच दिया है। अब इस राज्य में अदालती कार्यवाही पूरी तरह से तकनीक–आधारित और तेज होगी, जिसमें फाइलों और कागजों का इस्तेमाल न के बराबर रह जाएगा। शुक्रवार (1 मई) को राजधानी गंगटोक में आयोजित एक विशेष सम्मेलन के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने इस बड़े बदलाव की आधिकारिक घोषणा की।

इस ऐतिहासिक मौके पर सीजेआई सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि एक दौर था जब न्याय की आस में बैठे लोगों के लिए दूरी किलोमीटर में नहीं, बल्कि सफर के दिनों, खराब रास्तों और अनिश्चितताओं में मापी जाती थी। लेकिन आज बेहतर बुनियादी ढांचे और तकनीक ने पहुंच का पूरा स्वरूप ही बदल दिया है। डिजिटल राजमार्ग अब आम नागरिकों को सीधे विभिन्न न्यायिक मंचों से जोड़ रहा है और हम कागजी कार्यवाही के उस पुराने युग से बहुत आगे निकल चुके हैं। सिक्किम उच्च न्यायालय और सिक्किम न्यायिक अकादमी द्वारा 'प्रौद्योगिकी और न्यायिक शिक्षा' विषय पर आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन में देश भर के न्यायाधीश, कानूनी विशेषज्ञ और नीति निर्माता न्यायपालिका के डिजिटल कायाकल्प पर गहन मंथन कर रहे हैं।

कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी ने सिक्किम की इस बड़ी उपलब्धि की जमकर सराहना की। उन्होंने इसे एक उल्लेखनीय क्षण बताते हुए कहा कि यह तकनीक मानवीय फैसलों की जगह नहीं लेगी, बल्कि इसका मुख्य अर्थ उन भौतिक बाधाओं को हमेशा के लिए खत्म करना है जो न्याय में देरी का कारण बनती हैं। गुम होने वाली फाइलें, दस्तावेजों का ढेर और दूरी अब न्याय के आड़े नहीं आएगी। सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए. मोहम्मद मुस्ताक ने भी इस बदलाव को राज्य और भारतीय न्यायपालिका के लिए एक मील का पत्थर करार दिया। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ दिखावे के लिए हाई–टेक अदालतें बनाना नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर आम नागरिकों के जीवन में सीधा और सकारात्मक प्रभाव डालना है।

न्याय प्रणाली में इस तकनीकी क्रांति को लेकर सिक्किम हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति भास्कर राज प्रधान ने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल अदालतों को तेज, निष्पक्ष, सस्ता और अधिक मानवीय बनाने के लिए होना चाहिए। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस डिजिटल प्रगति के कारण समाज के हाशिए पर पड़े लोग अलग–थलग न पड़ जाएं। वहीं, सिक्किम के एडवोकेट जनरल बसवा प्रभु एस पाटिल ने बताया कि पेपरलेस होने का मतलब उन कागजों का अनादर करना नहीं है जिन पर हमारे संवैधानिक इतिहास और मिसालें दर्ज हैं। इसका असल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई पेज गुम होने, रिकॉर्ड न मिलने या फाइल के इंतजार में किसी भी आम नागरिक को न्याय के लिए भटकना न पड़े।

इस अहम सम्मेलन में भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमानी, जस्टिस रोनी जेम्स गोविंदन, सिक्किम उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय और राज्य के मुख्यमंत्री पी.एस. तमांग ने भी अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री तमांग ने इस उपलब्धि पर गर्व जताते हुए कहा कि सिक्किम एक राज्य के रूप में अपने 50 शानदार वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। ऐसे में सीजेआई सूर्यकांत और अन्य विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी में देश की पहली पेपरलेस न्यायपालिका की घोषणा और इस सम्मेलन की मेजबानी करना पूरे राज्य के लिए बड़े सम्मान की बात है।

अब तक 2,922 नाविक सुरक्षित वापस लाए गए, खाड़ी क्षेत्र में भारतीय ध्वज वाले जहाज पूरी तरह सुरक्षित–सरकार

नई दिल्ली, 03 मई।

सरकार ने शनिवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि अब तक 2,922 से अधिक भारतीय नाविकों (सीफेयरर्स) को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है, जिनमें पिछले 24 घंटों में 30 लोग खाड़ी क्षेत्र के अलग–अलग स्थानों से लाए गए हैं। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े अन्य पक्षों के साथ मिलकर नाविकों की सुरक्षा और समुद्री गतिविधियों को सुचारु बनाए रखने के लिए लगातार काम कर रहा है।

मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटों में किसी भी भारतीय ध्वज वाले जहाज से जुड़ी कोई घटना सामने नहीं आई है। डीजी शिपिंग कंट्रोल रूम ने अब तक 8,335 कॉल्स और 17,838 से अधिक ईमेल संभाले हैं। पिछले 24 घंटों में 67 कॉल और 144 ईमेल प्राप्त हुए।

बयान में आगे कहा गया है कि देश भर के बंदरगाहों पर कामकाज सामान्य रूप से चल रहा है और कहीं भी जाम (कंजेशन) की स्थिति नहीं है। विदेश मंत्रालय भी खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रहा है।

सरकार ने बताया कि समय–समय पर नई एडवाइजरी जारी की जा रही हैं, जिनमें स्थानीय नियम, यात्रा और उड़ानों की जानकारी, कांसुलर सेवाएं और अन्य सुविधाओं के बारे में बताया जाता है। भारतीय दूतावास वहां रह रहे भारतीयों और संगठनों से लगातार संपर्क में हैं और उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं।

उड़ानों की स्थिति धीरे–धीरे बेहतर हो रही है और खाड़ी क्षेत्र से भारत के लिए अतिरिक्त उड़ानें भी चलाई जा रही हैं। यूएई में सुरक्षा और संचालन के आधार पर सीमित कमर्शियल लाइट्स चल रही हैं। सऊदी अरब और ओमान से भी भारत के लिए नियमित उड़ानें जारी हैं।

सरकार ने बताया कि इराक का हवाई क्षेत्र सीमित उड़ानों के साथ खुला है, जिससे लोग भारत आ सकते हैं। ईरान का हवाई क्षेत्र आंशिक रूप से खुला है, जहां कार्गो और चार्टर्ड उड़ानें चल रही हैं। भारतीय नागरिकों को ईरान की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है और जो लोग वहां हैं, उन्हें भारतीय दूतावास की मदद से जमीनी रास्तों से वापस आने के लिए कहा गया है। अब तक तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने 2,490 भारतीय नागरिकों को ईरान से जमीनी रास्तों के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला है।–आईएएनएस

एम्स दिल्ली में बड़ी चिकित्सा उपलब्धिः देश का पहला पोर्टेबल एमआरआई सिस्टम शुरू

नई दिल्ली, 03 मई।

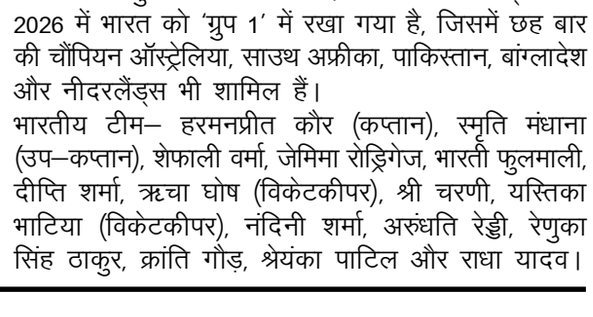

देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा कदम उठाते हुए भारत का पहला पोर्टेबल बेडसाइड एमआरआई सिस्टम शुरू किया है। यह अत्याधुनिक तकनीक गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए तेज और सुरक्षित ब्रेन इमेजिंग को संभव बनाएगी।

इस पोर्टेबल एमआरआई मशीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे सीधे मरीज के बेड तक ले जाया जा सकता है। पारंपरिक MRI स्कैन में मरीज को विशेष कक्ष तक ले जाना पड़ता है, जबकि नई प्रणाली ICU, इमरजेंसी और न्यूरोसर्जरी वार्ड में ही स्कैनिंग की सुविधा देती है। इससे गंभीर मरीजों को ट्रांसफर करने का जोखिम काफी कम हो जाएगा।

एम्स के सेंटर फॉर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में इस तकनीक का उपयोग शुरू हो चुका है। विशेषज्ञों की टीम डॉ. शैलेश गायकवाड़ के नेतृत्व में मरीजों की जांच कर रही है। डॉक्टरों के अनुसार, यह तकनीक स्ट्रोक, सिर की चोट, ICU मॉनिटरिंग, बच्चों के मामलों और सर्जरी के बाद की देखभाल में बेहद कारगर है।

विशेषज्ञों का कहना है कि अल्ट्रा–लो–फील्ड तकनीक पर आधारित यह पोर्टेबल MRI आपात स्थितियों में तेजी से निर्णय लेने में मदद करेगा, खासकर तब जब पारंपरिक इमेजिंग कराना कठिन या जोखिम भरा हो। इस पहल को नियामकीय मंजूरी मिलने के बाद लागू किया गया है, जिसमें Radiosurgery Global का सहयोग भी शामिल है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, यह पहल देशभर में ब्रेन इमेजिंग की पहुंच बढ़ाने के साथ पॉइंट–ऑफ–केयर न्यूरोडायग्नोस्टिक्स के क्षेत्र में शोध को नई दिशा देगी। इसे भारत के स्वास्थ्य तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में अहम उपलब्धि माना जा रहा है।

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का एलान

मुंबई, 03 मई।

भारत ने विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम घोषित कर दी है। यास्तिका भाटिया और राधा यादव की भारतीय टीम में वापसी हुई है, जबकि अनकैप्ड तेज गेंदबाज नंदिनी शर्मा को टीम में शामिल किया गया है। बीसीसीआई मुख्यालय में शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टीम की घोषित की गई, जिसमें कप्तान हरमनप्रीत कौर, मुख्य चयनकर्ता अमिता शर्मा और सचिव देवजीत सैकिया ने मीडिया को संबोधित किया। चयन समिति ने दिन की शुरुआत में बोर्ड मुख्यालय में बैठक की, जिसमें हरमनप्रीत और मुख्य कोच अमोल मजूमदार भी मौजूद थे। इस बैठक के बाद 15 सदस्यीय टीम को अंतिम रूप दिया गया। यही टीम 28 मई से 2 जून तक इंग्लैंड के खिलाफ तीन टी20 मुकाबले भी खेलेगी। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत को 'ग्रुप 1' में रखा गया है, जिसमें छह बार की चौंपियन ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नीदरलैंड्स भी शामिल हैं।

भारतीय टीम– हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप–कप्तान), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिगेज, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), श्री चरणी, यस्तिका भाटिया (विकेटकीपर), नंदिनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़, श्रेयंका पाटिल और राधा यादव।